Seventeenth Loksabha

an>

Title: Need to ensure timely completion of North Koel Reservoir Project in Bihar and Jharkhand -laid

श्री सुनील कुमार सिंह (चतरा): माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा झारखंड और बिहार में उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना के बकाया काम को 1,622.27 करोड़ रूपये के अनुमानित खर्च से पूरा करने की मंजूरी दिनांक 16 अगस्त 2017 को प्रदान की गयी थी । केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने तीन वित्त वर्षों के अन्दर 1622.27 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना के शेष बचे कार्यों को पूरा करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की थी । कैबिनेट ने परियोजना प्रबंधन सलाहकार (PMC) के रूप में जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा सरंक्षण मंत्रलाय के अधीनस्थ एक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम M/s WAPCOS Ltd. को टर्नकी आधार पर परियोजना के शेष बचे कार्यों के क्रियान्वयन को भी मंजूरी दी थी ।

दिनांक 05.01.2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा उत्तरी कोयल जलशाय परियोजना के शेष बचे कार्य का शिलान्यास पलामू (झारखंड) से किया गया । शुरू होने की तिथि से 30 महीने की अवधि में यह परियोजना पूरी की जानी है । परन्तु अभी तक डैम के शीर्ष पर फाटक लगाने का कार्य शुरू नहीं हुआ है । परन्तु डैम के निर्माण स्थल से लगभग 100 किमी. दूर स्थित बराज के नीचे नहर प्रणाली पर कार्य प्रारम्भ हो गया । यहाँ यह ध्यान देने कि बात है कि पहले भी डैम का कार्य पूर्ण होने से पूर्व ही नहर का कार्य हो चुका था । डैम कार्य को प्राथमिकता न देना और सुरक्षा की दृष्टि से तय किये गये कार्य पूर्ण नहीं करना लापरवाही का दृष्टांत है । डैम साइट घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र है । वहाँ सुरक्षा बल के तैनाती की दृष्टि से आवश्यक आधारभूत सरंचना खड़ी की जानी है । इस कार्य में WAPCOS Ltd. और राज्य सरकार एक दूसरे पर ज़िम्मेदारी थोप रहे हैं

। इसका त्वरित निदान कार्य को समयबद्ध अवधि में पूर्ण करने की दृष्टि से जरूरी है अन्यथा 42 वर्षों से लंबित योजना फिर अधर में लटक जायेगी । कार्य में बहुत अधिक विलंब हो रहा है । इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि यह परियोजना इस गति से निर्धारित समय पर पूर्ण नहीं हो पाएगी ।

अत: माननीय जल शक्ति मंत्री जी से मांग है कि उत्तर कोयल जलाशय परियोजना को निर्धारित समय पर पूरा करने की दिशा में शीघ्र ठोस सकारात्मक कदम उठाये जायें । साथ ही योजना से जुड़े सभी केन्द्रीय एवं राज्यों के अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों के साथ तत्काल एक समीक्षा बैठक आयोजित करें तथा कार्य की उच्च स्तरीय नियमित समीक्षा व देखरेख सुनिश्चित की जाये ।